***Date*:** 04-08-20
***Publication*:** The Times of India
***Edition*:** Kolkata

CIL posts 17% jump in July opencast output

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: Coal India has clocked a 17% growth in composite opencast production for July 2020 compared to the year-ago period.

This is a sum total of over burden removal (OBR) and the amount of coal produced through opencast means. The composite output was 110.40 million cubic metres (mcm) for July 2020 against 94.4 mcm in July 2019.

An official pointed out that for CIL which relies on opencast mines for 95% of its entire annual coal output, OBR is a crucial performance indicator which exposes the coal seam for future production at short notice. CIL's OBR alone in July 2020 surged ahead by 23.1% growth compared to July'19.

In volume terms, Northern Coalfields (NCL) accounted for more than a third of CIL's entire OBR registering a growth of 36.7% in July'20. NCL excavated 31.73 mcm of OBR in the month.

Coming back strongly, Mahanadi Coalfields (MCL) doubled its OBR this July to 12.4 mcm clocking a growth of 103% against 6.14 mcm in the last July. Bharat Coking Coal and South Eastern Coalfields posted growths of 25% and 21% respectively in removal of overburden.

The coal PSU despatched 43.4 million tonne (MT) of coal in July 2020, the highest for a month so far in the ongoing fiscal. CIL's coal sales in July20 compared to June20 increased by 1.8 MT registering 4.3% growth.

***Date*:** 04-08-20
***Publication*:** The Telegraph
***Edition*:** Kolkata

Coal India checks slide in output

A STAFF REPORTER

Calcutta: Coal India has put the brakes on the double-digit slide in production and offtake in the first three months of the fiscal. The public sector miner has produced 37.36 million tonnes (mt) in July, down 3 per cent compared with the corresponding month a year ago. Production was down 10.9 per cent in April, 11.3 per cent in May and 12.8 per cent in June.

Offtake during July was 43.39 mt, down 6.9 per cent over the corresponding month a year ago. The offtake during April, May and June were down 25.5 per cent, 23.3 per cent and 15 per cent, respectively.

Coal India officials said despite the Covid-induced slowdown and a three-day strike in the first week of July, the miner was able to ramp up its supplies for the month.

"Our production and offtake were weighed down by the Covid-led siege since the beginning of 2020-21. But for the first time in this fiscal the downward growth in a month fell below double digits in both the facets in July," said a senior executive, adding that production is expected to go up post monsoon.

***Date*:** 04-08-2020
***Publication*:** The Economic Times
***Edition*:** New Delhi

17% Jump in CIL's Composite Opencast Output in July

NEW DELHI State-owned Coal India Ltd (CIL) on Monday said it has clocked a 17% growth in composite opencast production in July over the same month a year ago. Further, the company is expecting the production to rise post monsoon in view of the positive growth trend in the Over Burden Removal (OBR). OBR implies removing top soil to expose the coal seams and make them mining ready. The composite production was 110.40 million cubic metres (M CuM) for July, against 94.4 M CuM in July 2019, CIL said in a statement.

***Date*:** 07-08-2020
***Publication*:** Prabhat Khabar
***Edition*:** Asansol

कोल इंडिया को घरेलू उत्पादन का मिला लक्ष्य

सांकतोड़िया. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को सरकार ने 2020-21 में 10 करोड़ टन कोयला आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन करने का लक्ष्य दिया है. सूत्रों ने बताया कि कंपनी को यह लक्ष्य ऐसे समय दिया गया है जब देश में एक तरफ घरेलू कोयले की प्रचूरता है, वहीं कोयले की मांग में गिरावट आयी है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कोल इंडिया को 2020-21 में कम से कम 10 करोड़ टन कोयला आयात के स्थान पर घरेलू गैर-कोकिंग कोल के उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है.'

अधिकारी के मुताबिक आयात किये जाने वाले कोयले के स्थान पर घरेलू कोयले के उपयोग को बढ़ाना देने के लिए कोल इंडिया कई अन्य गैर-निगमित क्षेत्रों को अपने से जोड़ रही है. इसमें सीमेंट, एल्युमीनियम और स्पॉन्ज आयरन शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी ने कई अतिरिक्त लागतों को हटा कर कोयले के लिए आरक्षित मूल्य शून्य किया है. गौरतलब है कि 2019-20 के दौरान देश ने 24.71 करोड़ टन कोयले का आयात किया. यह 2018-19 में आयातित 23.53 करोड़ टन से पांच प्रतिशत अधिक रहा था.

***Date*:** 2020-08-07
***Publication*:** Dainik Jagran
***Edition*:** Dhanbad

कोल इंडिया में 1818 पद पर बहाली को हरी झंडी

दैनिक जागरण एक्सक्लूसिव

आशीष अंबष्ठ • धनबाद

कोल इंडिया में इस साल 1818 लोगों की बहाली होगी। इनमें 1075 गैर वैधानिक और 743 वैधानिक पद शामिल हैं। वैधानिक पद में माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सुपरवाइजरी स्टॉफ शामिल है। पूरा प्लान कोल इंडिया ने तैयार कर लिया है। कोयला मंत्रालय ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। मंत्रालय ने इस साल के अंत तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दे दिया है। इससे पहले 1326 एमटी अधिकारी पद के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। अब साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

1075
गैर वैधानिक और 743 वैधानिक पद है शामिल

प्लान तैयार

- मंत्रालय ने इस साल के अंत तक प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश
- माइनिंग सरदार, सुपरवाइजरी स्टॉफ, ओवरमैन पर होगी बहाली

क्लीन कोल पर 20 प्रोजेक्ट : कोयला मंत्रालय के निर्देश पर कोल इंडिया ने 20 क्लीन कोल से संबंधित प्रोजेक्ट चालू करने जा रही है। इसमें कोल बेड मीथेन, वाशरी निर्माण आदि शामिल है। इसमें बीसीसीएल में प्रथम फेज में नौ वाशरी व द्वितीय चरण में दो और वाशरी का निर्माण होगा।

सोलर एनर्जी के 16 प्रोजेक्ट : कोल इंडिया की रिपोर्ट में 16 प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी, थर्मल व फर्टिलाइजर प्लांट के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में सीएमपीडीआइएल की मदद भी ली जा रही है। सीएमपीडीआइएल को कई प्रोजेक्ट में संयुक्त लिस्नेदारी के रूप में भी रखा है। सीएमपीडीआइएल में सोलर एनर्जी प्लांट बेहतर ढंग से काम कर रहा है।

14 नए प्रोजेक्ट के लिए 34 सौ करोड़ की मंजूरी

कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया में पांच साल के दौरान 329 नए प्रोजेक्ट चालू करने का प्लान तैयार किया है। जिसमें 99 प्रोजेक्ट भूमिगत खदानें होंगी। 14 नए प्रोजेक्ट को इस साल चालू करने की योजना है। इसके लिए 34 सौ करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। कोयला मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी गई है। इनमें बीसीसीएल, ईसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल के प्रोजेक्ट शामिल हैं। बीसीसीएल में सीबीएम प्रोजेक्ट को लेकर भी कोयला मंत्रालय ने भी हरी झंडी दे दी है। जो मुनीडीह में संचालित होगा।

***Date*:** 07-08-2020
***Publication*:** Hari Bhoomi
***Edition*:** Korba

कोल इंडिया ने आयात को शून्य पर लाने की पहल शुरू की

कोयले में आत्मनिर्भरता के लिए स्पेशल ई-नीलामी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कोरबा

कोलइंडिया ने कोयले के आयातकों के लिए ई-नीलामी की एक विशेष श्रेणी लांच की है। यह कोयला आयात को शून्य पर लाने के लिए सरकार की घोषणा के अनुरूप है। यानि कोयले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक पहल है।

कोई भी ग्राहक जिसने चालू वर्ष के दौरान कोयले का आयात किया है। वे उक्त ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। रोड सेल यानि सड़क परिवहन का उपयोग करने वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम बोली की मात्रा 25 हजार टन रखी गई है। रेल मोड का उपयोग करने वाली के लिए यह 50 हजार टन है। सीआईएल के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के लिए अपने कोयले की बिक्री बढ़ाने के लिए एक नया अवसर मिलने जा रहा है। ई-नीलामी एमएसटीसी और एम जंक्शन के माध्यम से होगी। कोल इंडिया जल्द ही अगस्त 2020-मार्च 2021 की अवधि के लिए नीलामी कैलेंडर की घोषणा करेगी। कोल इंडिया मिशन मोड के तहत आयातित कोयले को कम कर घरेलू आपूर्ति को बढ़ाएगी। इस प्रक्रिया में कंपनी ने घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों और गैर बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है। स्पंज आयरन, सीमेंट, कैप्टिव पॉवर उत्पादकों, उर्वरक उत्पादकों, स्टील और अन्य कन्ज्यूमर कोयला ले सकेंगे। स्पेशल ई-नीलामी सफल हुआ तो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की बचत होगी। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 150 मिलियन टन कोयले का आयात किया गया है। इसी सप्ताह सीएमडी मीट में कोल इंडिया प्रबंधन ने अनुषंगी कंपनी के सभी सीएमडी को स्पेशल ई-नीलामी की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी थी। तभी संकेत दे दिया गया था कि बहुत जल्द ही स्पेशल ई-नीलामी ऑफर लॉन्च किया जाएगा।

फाइल फोटो

क्वालिटी नहीं सुधरी तो नहीं मिलेंगे ग्राहक

जानकारों का कहना है कि घरेलू कोयले की क्वालिटी नहीं सुधरी तो नीलामी नहीं हो पाएगी। गुणवत्ता के मामले में विदेशी कोयला घरेलू कोयले से कई गुना बेहतर है। यही वजह है कि स्टील सेक्टर पूरी तरह आयातित कोयले से चल रहा है। घरेलू कोयले की स्थिति यह है कि देश की तीन बड़ी कंपनियों ने घरेलू कोयला लेने से इनकार कर दिया है। कोयले के आयात सिर्फ कोयले की कमी की वजह से नहीं होती है क्वालिटी कोयले की मांग पूरी करने के लिए भी कोयले का आयात किया जाता है और यह जरूरी जरूरत है। हार्डकोक को जरूरत भर घरेलू क्वालिटी कोयला दे नहीं पाते हैं। कई हार्डकोक यूनिट भी कभी-कभार आयातित कोयला लेती है।

***Date*:** 08-08-2020
***Publication*:** The Hindu Business Line
***Edition*:** Kolkata

Coal India allocation under e-auction rises 22%

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, August 7

Coal India Ltd (CIL) on Friday said that it logged a 21.5 per cent growth in coal allocation at 19.76 million tonnes (MT) under the four e-auction windows during the April-June quarter.

In the corresponding quarter a year ago, the fuel allocation by the PSU under all the four windows of e-auction was 16.26 MT, a CIL statement said. The four categories of e-auction are spot e-auction of raw coal, special forward e-auction for power producers, exclusive e-auction for non-power sector and special spot auction.

Booking by non-power sector witnessed a three-fold rise during April-June 2020 over the same period in 2019.

***Date*:** 09-08-2020
***Publication*:** Sanmarg
***Edition*:** Asansol

कोल इंडिया का कोई भी कोयला ब्लॉक कंपनी से अलग नहीं होगा : प्रमोद अग्रवाल

सांकतोड़िया : कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा है कि कोल इंडिया का कोई भी कोयला ब्लॉक कंपनी से अलग नहीं किया जाएगा। वाणिज्यिक खनन के लिए कोई भी ब्लॉक देने का प्रस्ताव भी नहीं है। कंपनी के पास प्रचुर मात्रा में कोल ब्लॉक है जो प्रतिस्पर्धा के दौर में भी कंपनी को अग्रणी रखेंगे। जानकारी के मुताबिक कोल इंडिया के पास 447 कोल ब्लॉक हैं। इनको हाल ही में 16 ब्लॉक, 10 कोल माइंस (विशेष प्रविधान) अधिनियम के तहत और छह खान खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत आवंटित किए गए हैं। इन 463 ब्लॉकों की संयुक्त क्षमता लगभग 170 बिलियन टन है। हाल ही में आवंटित किए गए 16 ब्लॉक में न्यूनतम 10 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता है जो अपने उच्चतम स्तर पर 264 मिलियन टन तक पहुंचेगी। उत्पादन की वर्तमान दर एवं अनुमानित वृद्धि के मद्देनजर कोल इंडिया देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में कोयला देने में सक्षम होगा। कोल इंडिया को 2023-24 तक एक बिलियन टन कोयले के उत्पादन और आपूर्ति का लक्ष्य दिया गया है। सीआइएल के पास चार दशकों की विशेषज्ञता रखने वाली सी ए म पी डी आ ई ए ल इकाई का होना निश्चित ही एक बड़ा स्पर्धात्मक लाभ है। सी ए म पी डी आ इ ए ल अन्वेषण, खान नियोजन, डिजाइन, बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ यह कोयला क्षेत्र के अन्य प्रतिभागियों पर अधिकांश कोयला खनन मुद्दों को हल करता है। कोल इंडिया के पास बहु-विषयक पेशेवरों की सम्पदा भी है। देश में कोयले की घरेलू मांग देश के कुल कोयला उत्पादन से ज्यादा है जिससे देश को कोयला आयात करना पड़ रहा है। इसके लिए विदेशी मुद्रा का भारी व्यय हो रहा। वाणिज्यिक खनन इस अंतर को पूरा करने के लिए एक कदम है जिससे कुछ हद तक कोयला के आयात को कम किया जा सकेगा। देश ने 2019-20 के दौरान 247 टन कोयले का आयात किया था जिसमें 52 टन कोकिंग कोल एवं 195 टन गैर-कोकिंग कोयला था। गौरतलब है कि कोल इंडिया जरूरत के मुताबिक अपना विस्तार करने में पूर्णतया सक्षम है। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कोल इंडिया अपनी परिचालन-कुशलता को लगातार बढ़ा रही है। उत्पादन एवं आपूर्ति को बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य और केंद्रीय निकायों के साथ मिल कर कार्य भी कर रही है।